



राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान  
National Institute of Design  
मध्यप्रदेश Madhya Pradesh

(An Institute of National Importance under DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India)

क्रमांक-रा0डि0सं0म0प्र0 / आरटीआई / प्रशा / 1-70 / 2022 / 01  
प्रति,

दिनांक 08.02.2022

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना बाबत।

प्रसंग:-आपकाऑनलाइन अनुरोध प्रार्थना पत्र क्रमांक एन.आइ.डी.एम पी./आर/ई/ 22/ 00002 दिनांक 11.01.2022 एवं तथा क्रमांक एन.आइ.डी.एम पी./आर/ई/ 22/ 00003 दिनांक 11.01.2022 राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान मध्य प्रदेश को प्राप्ति दिनांक 11.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्र के क्रम में आपके द्वारा राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान मध्य प्रदेश से चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार है।

क्र0सं0	बिन्दु संख्या	प्रत्युत्तर
01	01	चाही गयी सूचना अनुलग्न 01 में संलग्न है।
02	02	चाही गयी सूचना अनुलग्न 02 में संलग्न है।
03	03	चाही गयी सूचना अनुलग्न 03 में संलग्न है।
04	04	
05	05	साक्षात्कार हेतु कट ऑफ अंक 43 हैं।

02. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(8) (iii) की अनुपालना के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम तथा पत्राचार पता क्रमशः लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष कुमार बहुगुणा,(सेवानिवृत्त), कुलसचिव,राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान मध्य प्रदेश ग्राम अचारपुरा, पोस्ट अरवलिया ईट खेड़ी जिला भोपाल , मध्यप्रदेश पिन 462038 है।



श्री कृष्णा

(श्री कृष्णा बिरमान)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान मध्य प्रदेश

प्रतिलिपी:-

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी : कृपया अग्रिम कार्यवाही हेतु।  
राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान मध्य प्रदेश





8/10/2022 -1



राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान  
National Institute of Design  
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh

(An Institute of National Importance under DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Govt of India)

Answer Booklet No. [REDACTED]

13

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रदत्त  
Information given under RTI Act  
PART- II

28 Page

Application No.

NIDMP/DEPRE/00185

Name of the Candidate

Sudhakar Maurya

Father's/Mother's Name

Ram Dhani (Maurya)

Date of Birth

22-11-1985

Post Applied for

Deputy Registrar

Date of Examination

11-01-2022

No. of supplementary Copies

Marks obtained

Out of Total Marks

Signature of Invigilator

[Handwritten Signature]  
11/1/22





Answer - 01 to 10

1	(a)	X
2	(b)	X
3	(d)	(1)
4	(d)	(1)
5	(a)	X
6	(d)	X
7	(b)	X
8	(b)	X
9	(a)	(1)
10	(d)	(1)

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रदत्त  
- Information given under RTI Act

Total (4) ✓



11) (b) (1)

12) (b) X

13) (b) (1)

14) (b) (1)

15) (a) (1)

16) (d) (1)

17) (c) (1)

18) (d) (1)

19) (b) (1)

20) (b) X

सूचना अधिनियम के तहत प्रदात  
Information given under RTI Act

Total 8



Answer No- 21 to 40

- |    |   |                               |     |   |
|----|---|-------------------------------|-----|---|
| 21 | In year 2014 after 2019 through NISMSE, Make in India, Skill India 2014 |                               |     | X |
| 22 | HEP MP comes under DPET, headed by governing council                    |                               |     | X |
| 23 | Ministry of Education.  |                               |     | X |
| 24 | Free  |                               |     | X |
| 25 | <del>4.5 Lakh</del> . रोजगार सन्धि                                      |                               |     | X |
| 26 | 4.5 Lakh.   |                               |     | X |
| 27 | 3 C of CCS (Conduct) Rule 1964  |                               | (1) |   |
| 28 | University Grant Commission   |                               | (1) |   |
| 29 | NASCOM  |                               |     | X |
| 30 |   |                               |     |   |
| 31 | Make in India   | National Institute of Design. |     | X |

वर्ष 2014 के बाद 2019 के बाद NISMSE के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल इंडिया 2014' के अंतर्गत 4.5 लाख रुपये का निधि का प्रावधान किया गया है।



- 32 Centre for Excellence Y
- 33 Extra Preliminary Leave ID
- 34 X
- 35 B.Des with 03 specializations Communication Design, Textile Design, Inclusive Design ID
- 36 01.01.2004 X
- 37 2019 X
- 38 Government E-marketplace ID
- 39 All India Survey on Higher Education. ID
- 40

Q

प्राप्त जानकारी अधिनियम के तहत दी गई है  
 Information given under RTI Act

पृ. III  
 06



Answer No - 47

6

उत्पन्न शिक्षा के स-सर्व में सन 2020 का कामकाज का उत्पन्न वर्ष 1947-48 से ही प्रारम्भ होता हुआ प्रतीत होता है। सर्वप्रथम वर्ष 1968 में उत्पन्न वर्ष की सौच का विकास शिक्षा के क्षेत्र में परिभाषित होता जाकर आया था- कामकाज में 1986 में सर्वप्रथम से नए उत्पन्न शिक्षा नीति का यह है की Education Policy on Education का उत्पन्न हुआ। सुनी 34 वर्ष 39 वर्ष वर्ष - 2020 में उत्पन्न वर्ष उत्पन्न सौच के साथ National Education Policy या नए NEP-2020 जारी किया। तात्कालिक शिक्षा मंत्री रामेश प्रोवरिमान निम्नक मूल्यांकन के निर्देशन में जाति कमर्सी की अपाईर स्. के. कर्तरीरिजन द्वारा निम्नक सुच उत्पन्न 5+3+3+4, वर्ष 3 से लेकर 10 आयु वर्ष हेतु जारी किया जाति की उत्पन्न की जारी।

New education Policy की उत्पन्न उत्पन्न GEF (Gross Enrolment Ratio) को बढ़ाना तथा उत्पन्न जाति की उत्पन्न क्षेत्र व सहाय उत्पन्न उत्पन्न भी है जो उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न।

- GEF in Higher education reached at 50%. till 2035
- GEF in schooling education reached at 100%. till 2030
- GDP ratio 6%.
- 5+3+3+4, 3 to 10 year.
- Freshgraduate
- Diploma
- Degree



Graduation level degree course for 3 yrs or 4 yrs.  
of any candidate completed early year, he is entitled for certificate. If completed two year, get diploma and if he completed three years or 4 years, he ~~is~~ awarded degree.

In a higher education system, 23 numbers of IITs, 32 numbers of NITs, 85 numbers of IIITs under the Ministry of education funded, and other many CFTs. Approx. 120 CFTs are connected to his National Education Policy.

Q

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्राप्त  
Information given under PTA Act



Answer No - 48

Senate comes under the authority of National Institute of Design Act 2014. After the Governing Council, it is a esteemed body of National Institute of Design.

The vital role of senate to make ordinances for the purpose of academic ~~affairs~~ ~~if~~ curriculum, syllabus and how to the academic institution manage and give the quality education to enrolled students.

The senate is constituted with the following members.

- i) Director
- ii) Dean
- iii) two members among the Governing Council.
- iv) Head of Department.
- v) Any three members.

The proposal received from Academic Advisory Committee, regarding the academic, the senate, be considered and further put up with to governing council.

The senate only ~~make~~ ~~make~~ ordinances but it may be cancel



alter, modify and implemented only after the recommendation of governing council.

①

प्रश्न 2  
Information given under RTI Act



उपरजिस्टर (अकादमिक) से अपेक्षा इस महत्वपूर्ण कार्य निम्नवत है।

- 1 उपरजिस्टर (अकादमिक) को रजिस्ट्रार, मुख्य प्रश्न में कार्य शर्त किसी मान्यतापूर्वक Important Publication जैसे IIT, IIT या अन्य (CTA) में कार्य का अनुभव होना चाहिए जिससे उसे अकादमिक कार्य की कार्य शीलता शर्त स्पष्ट सशान में हो।
- 2 अकादमिक प्रणाली एवं प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए।
- 3 Academic Advisory Committee एवं Senaate में प्रस्तुत होने वाले मामलों पर उसकी विषय-वस्तु की जानकारी होनी चाहिए।
- 4 विभाग संरचना देने के लिए, विद्यार्थियों की समस्याओं को अलग-अलग प्राधिकारी तक निस्तारण Proposal के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।
- 5 विभाग से सम्बन्धी समस्त आवश्यक सूचनाओं को संस्थान के Records में रखें एवं अन्य उपरि पाठ्यक्रम से प्रसारित करवाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को कम से कम कोई भी असुविधा न हो।
- 6 विद्यार्थी सम्बन्धी शिकायतों के निस्तारण हेतु मामलों को तत्काल प्रतिक्रिया में लाना चाहिए।



2) शैक्षणिक सम्बन्धी निष्पत्तियों को सम्पादनार्थ अग्रगण्य कराने हेतु आगामी कार्यवाही श्रवण करनी चाहिये।

8) शैक्षणिक प्रक्रिया की जानकारी एवं समय-समय पर अस्सी अस्सी आधारन हेतु कार्यवाही करनी चाहिये।

9) वे समस्त कार्य जो NED मूल के Academic चीजों के कारण प्रभावित कर अग्रसर कर सकते हैं, प्रयासरत रहना चाहिये।

10) प्रिंट्स में भूषण, कुलसाचिव भूषण एवं इस संस्थान की समस्त कमिटी में आध्यात्मिक आनन्द के साथ इस संस्थान के विकास हेतु अग्रसर रहना चाहिये।

11) Academic के माध्यम से सर्वोच्च श्रेणी हेतु भारत सरकार की नीति का पालन करना एवं करवाना चाहिये।

2



(क) सर्वप्रथम टी.वी. चूना की खबर की संपत्ति की जांच का प्रयास केंद्रों की ओर दाय्य टी.वी. चूना द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं यह आशंक ही नहीं है। यदि यह खबरों साय प्रसारित होती है तो तर्कानुसार उन साक्षर चरणों की जांच केंद्रों जिससे माध्यम से यह खबर हुआ है। पूर्ववत् इस तरह की खबरों से बचने हेतु एक advance अग्रिम चेक की व्यवस्था रखेंगी। जिससे परीक्षा सेही समय पर सुभीकर तरीके से करवाया जा सके तथा इस मामले में अविवेक में ऐसा न हो जांच कमेटी के माध्यम से इसकी जांच तक आऊंगी।

(ख) यदि यह विषय विशेष कार्यक्रम के प्रवेश से सम्बन्धित है तथा प्राकृष्ट श्रेणी की जांच चुकी है इसलिये अभ्यासियों द्वारा जिकाएल की इस अनुसंधान ने साय साक्षर किता जांचना कि कर्मचारियों में प्रवेश सम्भाव नहीं है तथा यदि साय इस तरह की कोई विशेष कार्यक्रम हुआ। इस संस्थान द्वारा आयोगों किता जांचका तो इस संस्थान साय संस्थान के निर्देश से प्राप्त कर प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं।

(ग) सर्वप्रथम इस तरह के मामलों का निपटारा तर्कानुसार हो जाना चाहिये। यह संस्थान द्वारा के विकास हेतु ही है तथा इस तरह की जिकाएल मिम्व ही वह साक्षर प्रोपनिकेस ने आचार पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशन कर देना चाहिये। यदि मामला काफी और पकड़ लिया है तो द्वारा के साथ एक बॉर्डर साक्षर मामलों की गुरभरिदा को देखते हुए उनसे बात करने का प्रयास करूंगी और आश्वासन देना ही आवश्यक एवं सशुचिद कार्यवाही अवश्य की जायगी।







Answer No - 41

AISHE means All India Survey on Higher Education. The motto of this is to make a channel to know the students about the education standard and scholarship position of the institute concern. This is one type of code by which student get the details of concern after institute status of scholarship portal. The role of nodal officer to make ensure all the scholarship scheme will be available in respect of his institute, if not available make ensure that the student may get the correct details on national scholarship portal.

सर्व अधिकार अभिनिर्वाह के तहत प्रदान  
Information given under RTI Act



Answer No-45

Letter Head

(Bosehale Certificate)

Date

(To show it may be concern)

0

This is to certify that Mr. \_\_\_\_\_, student  
of first second third year enrolled an academic year  
for the course B.Design/ M.Des. Ph.D. is a  
Bosehale student of this Institute.

This certificate is issued for the academic year \_\_\_\_\_  
for the purpose of \_\_\_\_\_

Authority Name  
Designate with  
seal

सूचना अधिनियम के तहत प्रदात  
Information given under RTI Act



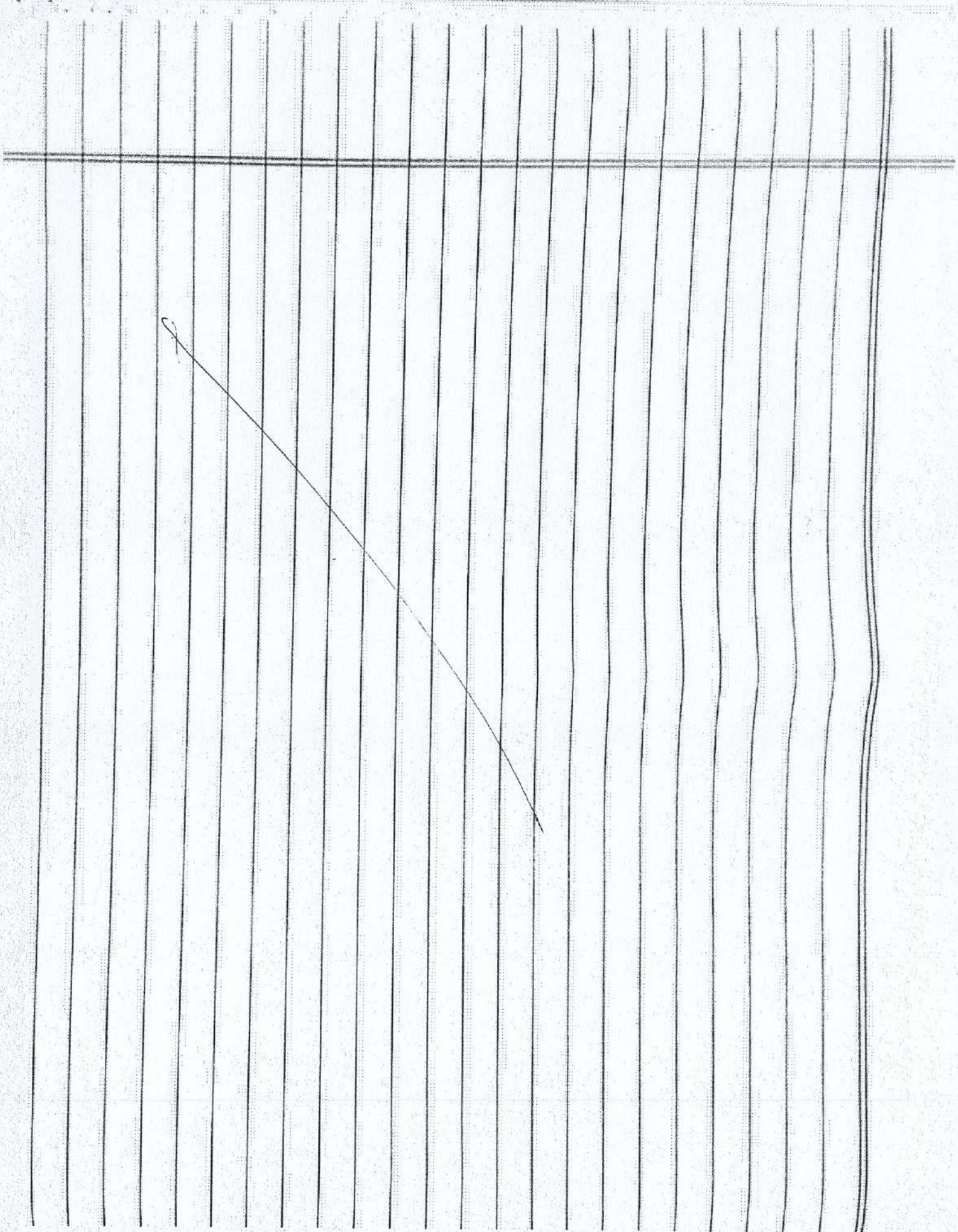
(a) Anti Ragging Committee

The main jurisdiction of Anti Ragging Committee to not make a place for all. No not behave or any other activities which show.

(1)

(b) Internal Complaints Committee - constituted for ~~the~~ to any the sexual harassment of women at workplace under the the act-2013 and vigilance guidelines.











राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्यप्रदेश  
National Institute of Design, Madhya Pradesh

उपकुलसचिव के लिए भर्ती परीक्षा  
Recruitment test for the position of Deputy Registrar

अधिकतम अंक : 100 Max Marks: 100 समय: 2 घंटे, Time: 2hours

**Model answer Key**  
**मॉडल उत्तर कुंजी**

भाग-1 अंग्रेजी  
Part-I English

(Q 01-10, 01 mark each)  
(प्रश्न 01-10, 01 अंक प्रत्येक)  
All questions are mandatory.  
सभी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है।

Q. 1 (c) Both a & b

Q. 2 (c) Both a & b

Q. 3 (d) QPSR

Q. 4 (d) Different

Q. 5 (d) Extol

Q. 6 (b) on

Q. 7 (a) We had got

Q. 8 (c) Contract

Q. 9 (a) A man who hates women

Q. 10 (d) The Registrar of NID, Madhya Pradesh is known to me



सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत  
Information given under RTI Act

भाग-2 मात्रात्मक योग्यता  
Part-II Quantitative Aptitude

(Q 11-20, 01 mark each)

(प्रश्न 11-20, 01 अंक प्रत्येक)

All questions are mandatory.

सभी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है।

- Q. 11 (b) 8
- Q. 12 (c) 3.876
- Q. 13 (b) Tuesday
- Q. 14 (b) 30 days
- Q. 15 (a) 6.25 %
- Q. 16 (d) 108
- Q. 17 (c) 12.86 sec
- Q. 18 (d) 1800
- Q. 19 (b) 12
- Q. 20 (a) 500

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत  
Information given under RTI Act

भाग-3 रिक्त स्थान भरें  
Part-III Fill in the Blanks

(Q 21-40, 01 mark each)

(प्रश्न 21-40, 01 अंक प्रत्येक)

All questions are mandatory.

सभी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है।

- Q. 21 11th Five Year
- Q. 22 Director
- Q. 23 Electronics & Information Technology



- Q. 24 Rs.1,500/-  
Q. 25 Raghavan  
Q. 26 6 Lakhs  
Q. 27 3-C  
Q. 28 University Grant Commission  
Q. 29 Anabin list  
Q. 30 e-FRRO  
Q. 31 India Design Council  
Q. 32 Teaching and Learning  
Q. 33 Extra Ordinary Leave  
Q. 34 Royal College of Arts  
Q. 35 Design  
Q. 36 01-04-2004  
Q. 37 1923  
Q. 38 Government e-market  
Q. 39 All India Survey on Higher Education  
Q. 40 FSSAI

भाग-4 वर्णनात्मक प्रश्न  
Part-IV Descriptive Questions

(Q 41-46, 10 mark each)  
(प्रश्न 41-48, 10 अंक प्रत्येक)  
Answer any 06 questions.  
किन्ही षॉच प्रश्नो का उत्तर दें।

- Q. 41  
i. Ministry of Education (MoE) initiated an All India Survey on Higher Education (AISHE) in the year 2010-11 with reference date of 30th September, 2010 to build a robust database and to assess the correct picture of higher Education in the country.



- ii. Objectives of the AISHE
  - (a) identify & capture all the institutions of higher learning in the country
  - (b) Collect the data from all the higher education institutions on various aspects of higher education
- iii. Data is being collected on following broad items
  - (a) Institution's Basic Details
  - (b) Teacher's Details
  - (c) Details of Non-Teaching Staff
  - (d) Programme conducted under various Faculties/Schools & Departments/Centres
  - (e) Students enrolled in these Programme
  - (f) Examination result of terminal year of each Programme
  - (g) Financial Information such as Receipt and Expenditure under various heads
  - (h) Availability of Infrastructure
  - (i) Scholarships, Loans & Accreditation

**Q. 42**

**a) Functions of the Anti-Ragging Committee**

- i. To ensure compliance with directions of the Hon'ble Supreme Court on the menace of ragging.
- ii. To prevent ragging in the institution.
- iii. To implement and coordinate anti-ragging measures.
- iv. To ensure anti ragging instructions are displayed at prominent places including canteen and hostels.
- v. To take appropriate action in case an incident of ragging is reported.
- vi. To make surprise raids on academic blocks/hostels and other places vulnerable to incidents of and having the potential of ragging.
- vii. To conduct on the spot enquiry/ take action into any incident of ragging, if noticed.
- viii. Maintain the record of the surprise visits.

**b) Functions of the Internal Complaints Committee**

The Internal Complaints Committee plays a pivotal role in the effective implementation of the provisions at the workplace.

Its major functions include:

- i. Implementation of the Anti-Sexual Harassment Policy at the workplace
- ii. Submit an Annual Report (Including details like the number of case files at their disposal, etc.)
- iii. Bring about awareness about what comprises 'sexual harassment' at the workplace by way of workshops, posters, documents, notices, seminars, etc.
- iv. Publicize the policy framework effectively
- v. Provide the victims with a safe and accessible mechanism of complaint
- vi. Initiation of inquiry at the earliest
- vii. Redress the complaints in a judicious manner



- viii. Provide interim relief to the complainant
- ix. Provide an opportunity for conciliation wherever possible
- x. Stick to the principles of natural justice at all stages of the proceedings
- xi. Whenever required, forward the complaint to the police
- xii. Submit the inquiry report along with recommendations.
- xiii. Maintain confidentiality in regard to the proceedings taking place before the Committee

**Q. 43** (Note: Suggested key points. Any related points also need consideration)

The Deputy Registrar (Academics) has to perform the functions related to:

- a) Academic and student affairs
- b) Examinations
- c) Admissions
- d) Course curriculum design
- e) Award of degrees
- f) Placement
- g) Academic manual
- h) Orientation/ Refresher programmes
- i) Industrial collaboration
- j) Hostel management
- k) Any other duty as assigned from time to time

(List is only suggestive. The elaboration in one or two sentences is sufficient.)

- Q. 44**
- a) Always the examination branch should have back up question papers. Nowadays with the development of technology, we can make use of it. The centre superintendent be informed of the cancellation of the paper sent to them for tomorrow's examination. New paper be mailed to them under secured method with a password and with instructions to use the revised paper in the place of old paper by getting xerox of the paper of the examination is online, the modified paper needs to be uploaded.  
Secondly, necessary inquiry needs to be conducted to find out the reasons for leakage so that the loopholes be plugged.
  - b)
    - i) The genuineness of the complaint needs to be verified thoroughly.
    - ii) If the candidates are really eligible in all respects, they should be given admission by creating necessary extra seats with the approval of authorities to avoid legal complications.
    - iii) It always happens some students may not join. Then the vacancies so caused be utilized.
    - iv) To look into the process and fix the loopholes for non-recurrence
  - c)
    - i) First step to speak with the students to find out the veracity of the complaint.
    - ii) If necessary, appoint a committee.
    - iii) The warden be cautioned, if necessary
    - iv) If there is some misunderstanding among the students and warden, it can be dispelled by making them sit together and explaining.
    - v) Once the root cause is found, action is to be taken for non-occurrence
  - d) **Orientation programmes** are arranged to orient the faculty
    - i) To the updates in the subject
    - ii) To new methods in teaching subject
    - iii) To the latest techniques
    - iv) As part of eligibility for their career advancement



These programmes help faculty to acquaint them with the latest developments in the knowledge fields in order to reorient themselves and to refresh their knowledge domain.

**Faculty induction programme** is arranged for the newly appointed teachers to enable them to know about the institutions, its objectives, its programmes, what is expected from, how they have to enable themselves in their teaching to achieve the targets and goals within the mandate of the institution.

- e) i) As far as seniority is concern the teachers are advised to approach the establishment branch of the institute which deals with the subject.  
ii) As far as CAS is concerned, they will be guided how they have to apply, what are the parameters they have to fulfill and all necessary guidance will be provided.

**Q. 45** Appended below is an indicative/common application format for applying for Bonafide Certificate:

To,

The Director/Registrar/Deputy Registrar,  
National Institute of Design,  
Madhya Pradesh

**Subject: Issue of Bonafide Certificate**

I, Mr./Ms. \_\_\_\_\_, student of \_\_\_\_\_ year/semester,  
\_\_\_\_\_ Discipline, pursuing B. Design course at National Institute of Design, Madhya Pradesh. I require a bonafide certificate from the institution for \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ purpose.

My particulars are listed below:

Name: \_\_\_\_\_

Roll No./Enrollment No.: \_\_\_\_\_

Father's Name: \_\_\_\_\_

Date of Birth: \_\_\_\_\_

Mobile: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Permanent

Address: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

I would kindly request you to consider my application and issue me a bonafide certificate as per details mentioned above.

Thanking you,

Yours Sincerely,

Date: \_\_\_\_\_

Signature of Student \_\_\_\_\_



**Q. 46** The primary role of the Institute Nodal officer is 1st Level verification of the applications submitted by applicants at NSP. The application form for students has been simplified with minimal uploading of scanned documents by students on NSP. Hence, the role of the Institute Nodal officer becomes very critical in the entire chain of verification process. The Institute Nodal officer using NSP must adhere to the following:-

- (i) Institute Registration Process
  - a. The Institute shall possess a valid AISHE code, before registering on NSP.
  - b. The Institute with valid AISHE code can register on NSP. To know whether an Institute is registered on NSP Portal or not, go to <https://scholarships.gov.in> and click on "Search Institute".
  - c. The Institute with valid AISHE code and not registered on NSP can request the District or State Nodal Officer, of any Scholarship scheme onboarded on NSP, to add it on NSP.
  - d. The District or State Nodal Officer will search for the Institute based on AISHE code. In case the institute is not registered, the Nodal Officer can add it by providing the requisite details. The system generated User credentials and password will be sent on the mobile number provided.
  - e. Colleges/Universities/Institutes/Schools and any other educational establishments onboarded on NSP shall be referred to as Institutes.
- (ii) Institute Nodal Officer: Registration process
  - a. From Academic Year 2019-20 onwards, Institute logging in the first time will have to mandatorily fill the Institute Nodal Officer Registration Form.
  - b. The Institute Nodal officer will login on NSP using the user credentials, and complete the Institute Nodal Officer Registration Form by entering his/her details and uploading the identity document. The Institute Nodal officer after locking the form using the OTP received, will take the print, paste his/her photograph on the Form, get it attested by the Institute Head (Signature and Institute seal/stamp), will submit the physical form to the respective District/ State/ Ministry Nodal officer of any scheme on-boarded on NSP.
  - c. The District/ State/ Ministry Nodal Officer will verify the physical form and the details entered in the system, and approve/reject the Institute Nodal Officer Registration Form details on NSP using the option "Verify Institute Registration Form" under the Administration section in his login. The User credentials and new password will be sent to the registered mobile number of the Institute Nodal officer. The original physical copy of the form should be kept with the District/ State/ Ministry Nodal Officer and a duplicate copy is to be shared with the Institute Nodal officer, who shall keep the same in the Institute's records.
  - d. The institute Nodal officer can login using the new User credentials, password and OTP received on his/her mobile number. The concerned officer can reset the password by clicking the "Forgot Password" on the Institute Login page on NSP.
  - e. For the cases of registration, where previous Institute Nodal has been transferred and has not provided the login credentials to the new Institute Nodal Officer, the new Institute Nodal Officer shall formally request District/ State/ Ministry Nodal Officer to change the mobile number and send the login credentials to the new mobile number. The new Nodal Officer is responsible for updating the profile with his/her credentials.
  - f. In case the new Institute Nodal Officer has access to the previous Nodal Officer, the registered mobile number can be changed by the existing Nodal



Officer. The system asks for the OTP on the previous mobile number and the new mobile number to be registered. The existing Nodal Officer is also primarily responsible for updating the profile with credentials of the new Nodal Officer.

- (iii) Institute Nodal Officer: Profile updation
- a. The Institute Nodal Officer shall submit the Institute details in the profile, and select the Course Levels offered by the Institute.
  - b. The Institute Nodal Officer shall ensure that the profile details of the Institute are updated from time to time.
  - c. The Institute Nodal Officer shall submit the correct bank account details of the Institute. d) The Institute Nodal Officer shall update the offered courses and course fee charged for each course Level.
  - d. The Institute Nodal Officer shall regularly change the password.
  - e. The Institute Nodal Officer shall ensure that the profile is updated profile with the details of the New Nodal officer before updating the mobile number and email ID, in case of change of Nodal officer.
- (iv) 1st Level Verification Process & Steps
- a. The Institute Nodal officer must verify the correctness of details in the application form and uploaded documents submitted by the student/ applicant, and maintain physical copies of supporting documents submitted by the student/ applicant. The District/State/Ministry Nodal Officer can ask for copies of these documents from the Institute Nodal Officers, as and when required.
  - b. The Institute Nodal officer has the option to either Verify the application, Reject the application or Defect the application. In case she/he chooses to Reject or Defect the application, the reasons for rejection or defect must be provided, so that the same can be displayed to the student/applicant. c) The Application defected by the Institute will be returned to student/applicant for correcting the same, and once submitted by the student/applicant, the application will be shown under Reverification section of NSP application.
  - c. The Institute Nodal Officer shall ensure that appropriate due diligence is done before verification of applications in accordance with the Scheme guidelines, and internal procedures as prescribed by Institute authorities / Government are followed.
  - d. The Institute Nodal Officer shall ensure that the applications are scrutinized well-in time by the Institute, thus avoiding the last-minute rush to verify the applications.
  - e. The Institute Nodal Officer shall ensure that there are no pending applications, as on the last date of L1 verification for that particular scheme, and all applications submitted by students/applicants to the Institute are scrutinized (verified/rejected/defected along with appropriate reason, as the case may be).
  - f. The Institute Nodal Officer can mark any application as Fake at any stage before the payment is made, using the option "Mark as Fake" under the Verification section in his/her profile in case a fraud is suspected in the application.



९  
सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रदत्त  
Information given under RTI Act

- Q. 47** (i) Increasing GER: The NEP aims to increase the GER in higher education to 50% by 2035 (GER was 26.3% in 2018). Institutions will have the option to run open distance learning and online programmes to improve access to higher education, which will improve GER in the country.
- (ii) Restructuring of institutions: All higher education institutions (HEIs) will be restructured into three categories:
- a. research universities focusing equally on research and teaching,
  - b. teaching universities focusing primarily on teaching, and
  - c. degree granting colleges primarily focused on undergraduate teaching. All such institutions will gradually move towards full autonomy - academic, administrative, and financial. All HEIs should eventually be transformed into large multidisciplinary universities and colleges with 3,000 or more students. By 2030, there should be one multidisciplinary HEI in, or near every district.
- (iii) Multidisciplinary education: The curricula of all HEIs should be made multidisciplinary to integrate humanities and arts with science, technology, engineering and mathematics. The undergraduate degree will be made more flexible with multiple exit options with appropriate certification. For example: students will receive a certificate after one year, diploma after two years, bachelor's degree after three years, and bachelor's with research degree after four years. Further, an academic bank of credit will be established to digitally store academic credits earned from various HEIs for awarding degrees based on credits. HEIs will have the flexibility to offer different designs of masters' programmes. The M.Phil. programme will be discontinued.
- (iv) Regulatory structure: The regulatory structure of higher education in India will be overhauled to ensure that the distinct functions of regulation, accreditation, funding and setting academic standards are performed by separate, independent bodies. This will minimise conflict of interest and eliminate concentration of power. To ensure this, the Higher Education Commission of India (HECI) will be setup with four independent verticals:
- a. the National Higher Education Regulatory Council as a single regulator (including teacher education, excluding legal and medical education),
  - b. the National Accreditation Council for accreditation of institutions,
  - c. the Higher Education Grants Council for financing of higher education institutions, and
  - d. General Education Council for specifying the curriculum framework and learning levels for higher education. Disputes between the four verticals will be resolved by a body of experts under the HECI.
- (v) Improving research: The Committee observed that investment on research and innovation in India is only 0.69% of GDP, compared to 2.8% in the USA, 4.2% in South Korea and 4.3% of GDP in Israel. The NEP recommends setting up an independent National Research Foundation for funding and facilitating quality research in India. Specialised institutions which currently fund research, such as the Department of Science and Technology, Indian Council of Medical Research will continue to fund independent projects. The Foundation will collaborate with such agencies to avoid duplication.
- (vi) Foreign universities: High performing Indian universities will be encouraged to set up campuses in other countries. Similarly, selected top global universities will be permitted to operate in India. A legislative framework facilitating such entry will be put in place. Such universities will be given exemptions from regulatory and governance norms on par with autonomous institutions in the country
- (vii) Vocational education: The Committee observed that less than 5% of the workforce in the age-group of 19-24 received vocational education in India during 2012-2017. This contrasts with 52% in the USA, 75% in Germany, and 96% in South Korea. The



NEP recommends that vocational education should be integrated in all school and higher education institutions in a phased manner over the next 10 years. A national committee for integration of vocational education will be set up under the MHRD for this purpose. The national skills qualifications framework will be detailed further for each discipline, vocation and profession. The NEP aims to ensure that at-least 50% of learners in school and higher education should be exposed to vocational education by 2025.

**Q. 48** The powers and functions of the Senate at NIDs mainly include:

- (i) framing and revising curriculum and syllabus for the courses of studies for various disciplines, as per the recommendations of the Academic Advisory Committee;
- (ii) making recommendations to the Governing Council with regard to the creation, restructuring or abolition of Disciplines or Programmes or Campuses;
- (iii) overseeing the arrangements for the conduct of examinations, appointment of examiners, moderators, tabulators and other matters relating to the examinations;
- (iv) declaring the results of final semester examinations or appointing Committees or Officers to do so and making recommendations to the Governing Council regarding conferment or grant of degrees, diplomas and other academic distinctions or titles;
- (v) appointing Committees or working Groups from amongst the members of the Senate, other faculty members and experts from outside to advise on specific and important academic matters;
- (vi) considering recommendations by Academic Advisory Committee and taking action or recommending a course of action;
- (vii) periodical review of activities of various faculty streams or disciplines and taking appropriate action for maintaining the excellence of standards of education of the Institute;
- (viii) promoting design research and development in class rooms and fields as also encouraging opportunities for bringing in market realities to the class rooms through consultancy, outreach and Industry Programme projects;
- (ix) planning and reviewing Electives and other extracurricular programmes of students and making appropriate recommendations;
- (x) overseeing the functioning of labs, studios, class rooms, hostels, student welfare, co-curricular activities and grievance mechanisms;
- (xi) awarding stipends, scholarships, medals, prizes and other similar recognitions with such conditions as may be deemed necessary;
- (xii) periodical review of the progress of various activities of the Institute;
- (xiii) constitute Admissions Committee to frame rules, eligibilities, formats, weightage and procedures, including outsourcing of various administrative and logistic activities through reliable and reputed agency or agencies for the conduction of admissions or entrance tests for various under-graduates and post graduate courses or programmes of the Institute and consider its recommendations for implementation;
- (xiv) inviting two student representatives to the Senate meeting during discussion of matters relating to student welfare, not involving any policy or disciplinary matters; and
- (xv) such other academic matters as may be referred to it by the Governing Council.



Sl No.	Application No.	Marks Scored (Out of 100)	Rank
1.	NIDMP/DEPRE/00534	64	1
2.	NIDMP/DEPRE/00433	58.5	2
3.	NIDMP/DEPRE/00306	56	3
4.	NIDMP/DEPRE/00504	51	4
5.	NIDMP/DEPRE/00731	51	4
6.	NIDMP/DEPRE/00237	48.5	5
7.	NIDMP/DEPRE/00488	45.5	6
8.	NIDMP/DEPRE/00321	44.5	7
9.	NIDMP/DEPRE/00461	44	8
10.	NIDMP/DEPRE/00721	43	9
11.	NIDMP/DEPRE/00809	42.5	10
12.	NIDMP/DEPRE/00309	42	11
13.	NIDMP/DEPRE/00199	41	12
14.	NIDMP/DEPRE/00531	41	12
15.	NIDMP/DEPRE/00379	40	13
16.	NIDMP/DEPRE/00495	39.5	14
17.	NIDMP/DEPRE/00390	39	15
18.	NIDMP/DEPRE/00035	38.5	16
19.	NIDMP/DEPRE/00185	36.5	17
20.	NIDMP/DEPRE/00744	36.5	17
21.	NIDMP/DEPRE/00467	35.5	18
22.	NIDMP/DEPRE/00737	35	19
23.	NIDMP/DEPRE/00790	35	19
24.	NIDMP/DEPRE/00046	34	20
25.	NIDMP/DEPRE/00072	32.5	21
26.	NIDMP/DEPRE/00815	32	22
27.	NIDMP/DEPRE/00004	31	23
28.	NIDMP/DEPRE/00357	31	23
29.	NIDMP/DEPRE/00057	28.5	24
30.	NIDMP/DEPRE/00460	28.5	24
31.	NIDMP/DEPRE/00849	28.5	24
32.	NIDMP/DEPRE/00548	25.5	25
33.	NIDMP/DEPRE/00513	24.5	26
34.	NIDMP/DEPRE/00544	23	27
35.	NIDMP/DEPRE/00787	23	27
36.	NIDMP/DEPRE/00604	17.5	28
37.	NIDMP/DEPRE/00507	16.5	29
38.	NIDMP/DEPRE/00500	11.5	30



